INTELLIGENTSIA
International Journal of Multidisciplinary Research
Volume (1), Issue (2)
July - September, 2025
Intelligentsia International Journal Of Multidisciplinary Research

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम

डॉ. मोहम्मद सरमद जमाल
प्राचार्य मगध कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, गया बिहार

सार :
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक और ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहु-विषयक और जीवनोपयोगी बनाना है, ताकि विद्यार्थी केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रहकर रचनात्मक, नैतिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक बन सकें। इस नीति में पाठ्यक्रम के स्वरूप को पुनर्परिभाषित करते हुए रटंत पद्धति की जगह अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, नवाचार और रचनात्मकता को केंद्र में रखा गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही कला, विज्ञान, व्यावसायिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच के कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर समग्र और बहु-विषयक शिक्षा पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा, सांस्कृतिक विविधता, नैतिक मूल्य और संवैधानिक आदर्शों को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी संसाधनों का उपयोग, शिक्षक प्रशिक्षण, सतत मूल्यांकन और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का समावेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं। संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा और पाठ्यक्रम को आधुनिक युग की मांगों के अनुरूप ढालने के साथ-साथ भारतीय जड़ों और वैश्विक दृष्टि के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास है, जो भारत को ज्ञान-आधारित और आत्मनिर्भर समाज की ओर अग्रसर करेगा।

कुंजी शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पाठ्क्रम,शिक्षा

प्रकाशन समयरेखा:
मूल पाण्डुलिपि प्राप्त – 20 जुलाई, 2025; सहकर्मी समीक्षण पूर्ण – 30 जुलाई, 2025; संशोधित पाण्डुलिपि प्राप्त – 03 अगस्त, 2025; स्वीकृत एवं प्रकाशित – 05 अगस्त, 2025
अनुशंसित संदर्भ
जमाल, एम. एस. (2025). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम. इंटेलिजेंटसिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 1(2), 37–42 .

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो समग्र, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देती है। यह नीति 21वीं सदी के कौशलों, जैसे डिजिटल साक्षरता, कोडिंग, और रचनात्मक सोच, को प्राथमिक स्तर से पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर देती है (कुमार, 2021)[1]। NEP 2020 भारतीय ज्ञान परम्परा, जैसे योग और वैदिक गणित, को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है, ताकि सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का संतुलन हो। यह लचीलापन और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देती है । यह नीति बहुभाषी शिक्षा और समावेशिता पर भी केंद्रित है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री विकास की आवश्यकता बढ़ी है। इस अध्ययन का उद्देश्य है: NEP 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम नवीनीकरण की प्रक्रिया, विशेष रूप से भारतीय ज्ञान परम्परा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करना।

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 –विजन

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है - जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और निष्ठापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित - समावेशी, और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। एक अच्छी शैक्षिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि, साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मूलभूत सिद्धांत

सिद्धांत	प्रमुख बिंदु
समानता और समावेशन	- हर बच्चे की क्षमताओं की पहचान व विकास - शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाना - शिक्षा को मौलिक अधिकार मानना
बुनियादी कौशल और गुणवत्ता	- प्राथमिक स्तर पर साक्षरता और संख्याज्ञान को प्राथमिकता - रटंत पद्धति के बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर - सतत एवं समग्र मूल्यांकन
बहु-विषयक और समग्र दृष्टिकोण	- कला, विज्ञान, व्यावसायिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच भेद समाप्त - बहु-विषयक शिक्षा का विकास - नवाचार, रचनात्मकता और तार्किक सोच को बढ़ावा
मूल्य और चरित्र निर्माण	- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का समावेश - जीवन कौशलों का विकास: संवाद, सहयोग, नेतृत्व, जिम्मेदारी

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

भाषा और सांस्कृतिक विविधता	- बहुभाषिकता को प्रोत्साहन - स्थानीय संदर्भों का सम्मान - भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से प्रेरणा
शिक्षक और संस्थागत सशक्तिकरण	- शिक्षक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र मानना - भर्ती, प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास - पारदर्शिता और प्रभावी नियामक ढांचा
तकनीक और संसाधन	- अध्ययन-अध्यापन और प्रबंधन में तकनीक का उपयोग - दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना - आधारभूत संरचना और सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करना

विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)[2] विद्यालयी शिक्षा को समग्र, एकीकृत, आनंददायी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने पर बल देती है। नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं या रटंत पद्धति तक सीमित न रखकर उन्हें आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों से युक्त बनाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम को इस प्रकार पुनर्गठित किया गया है कि यह बच्चों की संज्ञानात्मक और विकासात्मक अवस्थाओं के अनुरूप हो। NEP 2020 ने विद्यालयी शिक्षा को 5+3+3+4 के नए ढाँचे में व्यवस्थित किया है, जो क्रमशः फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के रूप में विभाजित है। इस ढाँचे का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला बनाना, विषयों के बीच की कृत्रिम दीवारों को समाप्त करना और बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। नीति में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र को इस तरह तैयार करने की बात कही गई है कि विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी कौशल, मूल्य और ज्ञान प्राप्त हो सके। फाउंडेशन स्तर पर खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षा, प्रिपरेटरी स्तर पर संवादात्मक शिक्षण, मिडिल स्तर पर विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से अवधारणात्मक अधिगम और सेकेंडरी स्तर पर बहुविषयक, गहन व आलोचनात्मक अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को भी महत्व दिया गया है। इस प्रकार विद्यालयी पाठ्यक्रम का पुनर्गठन बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा, रुचि और क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदार नागरिकता के लिए तैयार करने का एक दूरदर्शी प्रयास है।

1. फाउंडेशन स्टेज (5 वर्ष, आयु 3–8 वर्ष)

फाउंडेशन स्टेज में तीन वर्ष आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल और दो वर्ष प्राथमिक कक्षा 1–2 को शामिल किया गया है। यह चरण बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) पर आधारित है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम का फोकस बच्चों के समग्र विकास पर है, जिसमें खेल, कहानी, चित्रकला, नृत्य, संगीत और गतिविधि-आधारित शिक्षण शामिल हैं। यहाँ बच्चों को औपचारिक शिक्षा में धकेलने के बजाय उनकी जिज्ञासा, भाषा विकास, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक व्यवहार और शारीरिक कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है। पढ़ना, लिखना और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी दक्षताओं की नींव इसी स्तर पर रखी जाती है। शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह आनंददायी और खोजपरक होता है, ताकि बच्चों में सीखने के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा हो।

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

2. प्रिपरेटरी स्टेज (3 वर्ष, आयु 8–11 वर्ष, कक्षा 3–5)

प्रिपरेटरी स्टेज बच्चों को धीरे-धीरे औपचारिक शिक्षा की ओर ले जाने का चरण है। इसमें गतिविधि-आधारित और संवादात्मक शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों से परिचित कराया जाता है। यहाँ पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है कि बच्चों की तार्किक क्षमता, रचनात्मकता और संवाद कौशल विकसित हो सकें। किताबों का उपयोग शुरू तो होता है, किंतु यह केवल माध्यम भर है; शिक्षा का केंद्र बिंदु अनुभव, प्रयोग और संवाद रहता है। इस स्तर पर पढ़ाई अधिक संरचित होती है, जिससे बच्चे आगे के जटिल विषयों के लिए तैयार हो सकें।

3. मिडिल स्टेज (3 वर्ष, आयु 11–14 वर्ष, कक्षा 6–8)

मिडिल स्टेज में विद्यार्थियों को विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों से पढ़ाया जाता है। इस स्तर पर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाता है। यहाँ अवधारणात्मक अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों को केवल जानकारी देने के बजाय उनसे प्रश्न पूछने, खोजबीन करने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की भी शुरुआत होती है ताकि बच्चों को भविष्य की रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रारंभिक अनुभव मिले। अनुभव-आधारित और प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे विषयों के बीच अंतर्संबंध स्पष्ट हो सके और विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझकर समाधान खोजने में सक्षम बनें।

4. सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष, आयु 14–18 वर्ष, कक्षा 9–12)

सेकेंडरी स्टेज दो फेज़ में विभाजित है – कक्षा 9–10 और कक्षा 11–12। इस चरण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गहन और बहुविषयक अध्ययन की सुविधा देना है। यहाँ विद्यार्थियों को अपनी रुचि और करियर आकांक्षाओं के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, अनुसंधान और जीवन कौशलों के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं रखा गया है; विद्यार्थी चाहें तो व्यावसायिक शिक्षा को भी अन्य विषयों के साथ चुन सकते हैं। इस स्तर पर शिक्षा केवल परीक्षाओं तक सीमित न होकर उच्च शिक्षा और जीवन के लिए तैयारी का माध्यम बनती है। इस चरण में विद्यार्थियों को नागरिकता, नैतिकता, वैश्विक दृष्टिकोण और नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण बनाने पर बल दिया गया है।

3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : 5+3+3+4 ढाँचा

चरण	आयु समूह	कक्षा	अवधि	मुख्य विशेषताएँ
फाउंडेशन स्टेज	3–8 वर्ष	आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल (3 वर्ष) + कक्षा 1–2	5 वर्ष	खेल एवं गतिविधि-आधारित अधिगम, ECCE पर आधारित शिक्षा, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक व शारीरिक कौशल की नींव
प्रिपरेटरी स्टेज	8–11 वर्ष	कक्षा 3–5	3 वर्ष	संवादात्मक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण, पढ़ना-लिखना, गणित, भाषा, कला, संगीत,

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

				शारीरिक शिक्षा और विज्ञान की प्रारंभिक समझ
मिडिल स्टेज	11–14 वर्ष	कक्षा 6–8	3 वर्ष	विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा पढ़ाई, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल व व्यावसायिक शिक्षा, अनुभव-आधारित अधिगम, विषयों का अंतःसंबंध
सेकेंडरी स्टेज	14–18 वर्ष	कक्षा 9–12 (दो फेज़ : 9–10 और 11–12)	4 वर्ष	बहु-विषयक अध्ययन, विषय चयन में लचीलापन, गहन अध्ययन, आलोचनात्मक चिंतन, जीवन आकांक्षाओं पर ध्यान, व्यावसायिक/विशेषज्ञता आधारित शिक्षा का विकल्प

क्रियान्वयन सम्बन्धी चुनौतियाँ एवं समाधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती मानकीकरण और विविधता के बीच संतुलन की है, क्योंकि भारत जैसे विशाल और बहुलतावादी देश में सभी राज्यों और क्षेत्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करना व्यावहारिक नहीं है (राजू,2022)[3]। दूसरी चुनौती है शिक्षक-प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, क्योंकि अधिकांश शिक्षक नई बहुविषयक, कौशल-आधारित और तकनीक-संवेदी शिक्षण शैली से पर्याप्त परिचित नहीं हैं (वेंकटेश्वरलु, 2021)[4]। तीसरी चुनौती आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहाँ डिजिटल उपकरण, इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता अब भी सीमित है (सक्सेना, 2021)[5]। चौथी समस्या है आर्थिक असमानता और सामाजिक विविधता, जिसके कारण हर छात्र समान अवसर नहीं पा सकता। इसके अतिरिक्त, नीति के प्रावधानों को लागू करने में राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय, सतत निगरानी और पारदर्शिता भी एक गंभीर चुनौती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बहुस्तरीय प्रयास आवश्यक हैं। सबसे पहले, राज्यवार लचीलेपन के साथ पाठ्यक्रम लागू किया जाए, ताकि स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो सके। शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र और सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाएँ। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा, शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित कर प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। नियमित मूल्यांकन, ऑडिट और जनसहभागिता से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। यदि इन चुनौतियों का समाधान समन्वित प्रयासों से किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन न केवल सफल होगा, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकेगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को केवल जानकारी देने की प्रक्रिया न मानकर, उसे जीवन निर्माण और समाज परिवर्तन का साधन मानती है। यह नीति विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ-साथ मानवीय मूल्य, वैश्विक दृष्टि और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह शिक्षा को

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

स्थानीयता और वैश्विकता के बीच सेतु बनाती है—जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति और परंपराओं से प्रेरणा ली जाती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। नीति का ढांचा शिक्षा को चरणबद्ध रूप से बच्चे के विकास के अनुरूप ढालता है, जिससे उसकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। यह केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की ओर भी विद्यार्थियों को अग्रसर करती है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के लिए एक नवयुगीन शैक्षिक दर्शन प्रस्तुत करती है, जो ज्ञान, कौशल, नैतिकता और समावेशिता का संतुलित मेल है। यदि इसे योजनाबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाएगी, बल्कि राष्ट्र को ज्ञान-आधारित समाज और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाएगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. कुमार, ए. (2021). न्यू एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020: अ रोडमैप फॉर इंडिया 2.0. *यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा (USF) M3 पब्लिशिंग*, 3(2021), 36.
2. भारत सरकार. (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. *मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट.*
3. राजू, बी. (2022). कमेंट ऑन न्यू स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर एनविसेज्ड इन एनईपी 2020. *जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस*, 10(11), 294-298.
4. वेंकटेश्वरलु, बी. (2021). अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ एनईपी 2020: इश्यूज़, अप्रोचेज़, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रिटिसिज़्म. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च*, 10(2), 191-196.
5. सक्सेना, ए. (2021). द ग्लिम्प्स ऑफ एनईपी 2020. *मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च*, 2, 1-5.

****

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved